**भारत सरकार**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**

**लोकसभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या. 2498**

**(सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)**

**भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान के साथ सहयोग**

**2498. श्री विजय कुमार दूबेः**

**श्री प्रताप चंद्र सारंगीः**

क्या **कारपोरेट मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के बीच सहयोग के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) राष्ट्रीय सूचकों को राज्य सूचकों के साथ किस प्रकार एकीकृत/समन्वयित करने का प्रस्ताव है,

(ग) इस एकीकृत/समन्वित रोडमैप से राज्यों के सतत विकास कार्यों और व्यापार को राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाने में किस प्रकार सहायता मिलने की संभावना है; और

(घ) यह एकीकृत सूचक प्रणाली साक्ष्य पर आधारित नीति बनाने को किस हद तक मज़बूत करेगी और यह विकसित भारत के विज़न को पूरा करने में किस तरह मदद करेगा?

**उत्तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।**

**(श्री हर्ष मल्होत्रा)**

(क) से (घ): कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्थान, भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) संरेखण ढांचा विकसित करना राष्ट्रीय, राज्य, पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) और कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) संकेतकों को एकीकृत करना' पर एक शोध अध्ययन को मंजूरी दी गई है। उपरोक्त के बीच एक समझौता ज्ञापन पर 31 अक्टूबर, 2025 को हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए राज्य एसडीजी फ्रेमवर्क के साथ सीएसआर और ईएसजी परियोजनाओं/व्यवसायों की पहलों को संरेखित करते हुए राज्य विशिष्ट एसडीजी प्रगति संकेतकों का मूल्यांकन और पहचान करना, सीएसआर से संबंधित कार्यकलापों पर रिपोर्ट करने के लिए राज्यों के लिए एक मानकीकृत तंत्र का सुझाव देना और एसडीजी एजेंडा के तहत भारत के कारपोरेट क्षेत्र और इसकी राष्ट्रीय और वैश्विक प्रतिबद्धता के बीच तालमेल बनाने के लिए एक रोडमैप प्रदान करना है। अध्ययन अभी शुरू होनी है।